संख्या:395/2023/994/35-4-2023/35-4099/41/2023

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कासगंज ।

नियोजन अनुभाग-4 दिनांक: 26 मार्च, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विधान सभा क्षेत्रों में राजकीय आई0टी0आई0 की स्थापना किये जाने से संबंधित मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद जौनपुर, चित्रकूट, फतेहपुर, कासगंज, संतकबीर नगर, गाजीपुर, ललितपुर, बागपत, मथुरा एवं अलीगढ़ की विधान सभा क्षेत्रों में राजकीय आई० टी० आई० के भवन निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-37/2020/508/35-4-2020, दिनांक 28 मार्च, 2020 द्वारा 10 कार्यों में से 01 कार्य (शासनादेश के क्रमांक-4 पर अंकित कार्य) की रू. 1257.49 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में रू.503.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-177/2021/1682/35-4-2021, दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा रू. 125.75 लाख एवं शासनादेश संख्या-249/2022/865/35-4-2022/001-35-4099/48/2022, दिनांक 10 अगस्त, 2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रु. 314.37 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। इस प्रकार उक्त कार्य हेतु अब तक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में कुल रु.943.12 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिलाधिकारी कासगंज द्वारा उक्त 01 कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का पूर्ण व्यय होना इंगित गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए देय चतुर्थ किश्त के रूप में 20 प्रतिशत धनराशि रू.251.50 लाख (रूपये दो करोड़ इक्यावन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

((रू. लाख में)

कार्य का नाम	**अनुमोदित लागत**	**पूर्व मे अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
राजकीय आई0टी0आई0, विधान सभा क्षेत्र-आमापुर के ग्राम मोहनपुर देहात, कासगंज का भवन निर्माण कार्य।	1257. 49	943.12	251.50

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2020, दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 एवं दिनांक 10 अगस्त, 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. 2,51,50,000 (रूपये दो करोड़ इक्यावन लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-203-रोजगार-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0302-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 395/2023/994(1)/35-4-2023/35-4099/41/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, अलीगढ मण्डल।
8- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास), एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज ।
11-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी कासगंज ।
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कासगंज ।
14- संबंधित अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कासगंज।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।